



गुस्ताव क्लिम्ट की अंतिम कलाकृति इस माह के अंत तक नीलाम होने वाली है और पूरी संभावना है कि यह यूरोप की सबसे महंगी पेंटिंग बन सकती है। विना के इस कलाकार ने सन् 1918 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले "लेडी विद फैन" नाम की यह पेंटिंग पूरी की थी। गत 30 साल से यह अविशान के लिए नहीं आई है। अब लंदन में सोथबीज इसकी नीलामी करने जा रहा है और उम्मीद है कि यह तकरीबन 8 करोड़ डॉलर में बिकेगी। गुस्ताव क्लिम्ट अपने अंतिम वर्षों में एक प्रतिष्ठित पेंटर बन चुका था और पोर्ट्रेट बनाने में उसे महारथ प्राप्त थी। लेकिन "लेडी विद फैन" उसकी अन्य कलाकृतियों से अलग है। विशेषज्ञ कहते हैं कि, क्लिम्ट को यह पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी ने दिया नहीं था, उसने सिर्फ अपनी खुशी के लिए यह कलाकृति बनाई थी। विना की महिलाओं को मादक अंदाज में दर्शाना उसका प्रिय विषय था। सोथबीज की हैलेना न्यूमैन ने कहा कि, पोर्ट्रेट में चित्रित महिला किसी की बेटी नहीं थी जो क्लिम्ट के पास अपना पोर्ट्रेट बनवाने गई थी, बल्कि यह तो क्लिम्ट का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें वह सीमाओं को तोड़ देना चाहता था। अपने पूरे करियर में क्लिम्ट अपने समकालीन कलाकारों के बीच विवादों का केन्द्र बना रहा। उसने "विना सिसेशन मूवमेंट" की स्थापना की और अकैडमिक आर्ट के खिलाफ बगावत की थी। उसने अलंकारिक शैली को ज्यादा तवज्जो दी। इसका जिज्ञा एनसायक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में भी है। उसकी कलाकृतियों में ब्राइट पेंट्स व रंग नजर आते हैं, जो तत्कालीन पारम्परिक शैली से अलग थे। यह पेंटिंग भी अपवाद नहीं है, जिसकी पृष्ठभूमि में रंग बिरंगी चिड़ियाँ, कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं, तथा पेंटिंग में नजर आ रही सी ने किमोनो पहन रखा है। पेंटिंग हाल ही में विना के अपर बेलवडियर म्यूजियम में प्रदर्शित की गई थी। क्लिम्ट ने 1890 के दशक में एशियन आर्ट की पढ़ाई की थी और खासकर जापानी कला में उसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। क्लिम्ट ने चीन, कोरिया, पर्शिया व भारतीय कला शैली का भी अध्ययन किया था। "लेडी विद फैन" में चीन व जापान का प्रभाव नजर आता है। इसमें जापान के बुड ब्लॉक पोर्ट्रेट का असर भी देखा जा सकता है, उनमें भी महिला को ऐसी ही मुद्राओं में दर्शाया जाता है।

अमेरिका के प्यू रिसर्च सैन्टर का सर्वे काफी रोचक है

सर्वे के अनुसार, हालांकि, ज्यादातर अमेरिकी भारत के बारे में अच्छा सोच रखते हैं, पर, कईयों ने मोदी का नाम नहीं सुना

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। भारतीय प्रधानमंत्री शुरुआत को अमेरिका पहुंचे, पर उससे पहले हुए एक सर्वे में मोदी के बारे में पूछे जाने पर अधिकांश युवा अमेरिकन का यही जवाब था, कौन है मोदी?

मोदी की यात्रा से पूर्व प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे करवाया, जिसमें पाया कि हालांकि अमेरिकन लोग आमतौर पर भारत को पसंद करते हैं, पर अधिकांश ने मोदी के बारे में नहीं सुना था, और जिन्होंने उनके बारे में सुना था, वे उनमें भरपूर नहीं करते हैं। अमेरिका के 40 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी भी मोदी के बारे में नहीं सुना। यही नहीं 30 वर्ष से कम उम्र के 59 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे मोदी को नहीं जानते और 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 28 प्रतिशत लोगों ने भी मोदी के प्रति अनभिज्ञता जताई। उच्च शिक्षित को तुलना में ऐसे कम शिक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है जिन्होंने मोदी के बारे में कभी नहीं सुना।

लेकिन सरकार द्वारा मोदी का जो भारी स्वागत किया गया है और उसको मीडिया में जो शानदार कवरेज मिला है और मोदी और बाइडन के बीच हुई

- 59 प्रतिशत युवा अमेरिकी, जिनकी आयु तीस वर्ष से कम है, ने सर्वे में बताया कि, वे नहीं जानते मोदी कौन हैं।
- जब अमेरिका वासियों को भारत का झण्डा दिखाया गया तो, केवल 41 प्रतिशत लोग सही उत्तर दे सके कि, यह हिन्दुस्तान का झण्डा है।
- 51 प्रतिशत अमेरिकियों का भारत के प्रति सकारात्मक सोच, पर 44 प्रतिशत का नकारात्मक सोच है।
- डेमोक्रेटिक पार्टी या डेमोक्रेटिक सोच से इतफाक रखने वाले लोग भारत के प्रति ज्यादा सकारात्मक सोच रखते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों की तुलना में।
- 23 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं, भारत का प्रभाव बढ़ा है विश्व में, पर 11 प्रतिशत मानते हैं कि, प्रभाव घटा है। 64 प्रतिशत मानते हैं, प्रभाव में खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

द्विपक्षीय वार्ताओं व दोनों देशों के बीच हुए रक्षा, स्पेस व तकनीकी समझौता से इस धारणा में थोड़ा बदलाव आ सकता है। इसके अलावा सर्वे कहता है कि जिन्होंने मोदी के बारे में सुना था वे उनमें से अधिकांश के प्रति नकारात्मक धारणा रखते थे। शोध में शामिल 37 प्रतिशत लोगों को विश्व मामलों में कुछ सही कर पाने की उनकी क्षमता पर संदेह है, सिर्फ 25 प्रतिशत को उन पर भरोसा है। अधिकांश अमेरिकन भारतीय झंडे के बारे में नहीं जानते, वर्ष 2022 में अमेरिकन की अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर जानकारी के लिए हुए टेस्ट में तिरंगे झंडे की तस्वीर दिखाई गई थी, तब सिर्फ 41

प्रतिशत ने सही जवाब दिया था। स्नातक डिग्री या उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के भारतीय झंडे की सही पहचान करने की संभावना ज्यादा थी। साथ ही बुजुर्गों की तुलना में युवा वर्ग भारतीय झंडे को सही पहचान करने में ज्यादा सक्षम है। सर्वे के अनुसार केंजर्वेटिव रिपब्लिकनस की तुलना में 16 प्रतिशत उदार डेमोक्रेट्स ने भारतीय झंडे को पहचाना। अमेरिका के लगभग 51 प्रतिशत वयस्क भारत के प्रति अच्छी राय रखते हैं वहीं इससे कुछ कम 44 प्रतिशत की राय भारत के प्रति अच्छी नहीं है। शिक्षा के अनुसार भी सोच प्रभावित हुई है। स्नातक या उससे ज्यादा शिक्षित 55

प्रतिशत अमेरिकनस भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं वहीं कॉलेज जाने वाले 50 प्रतिशत लोगों की सोच भी ऐसी है। डेमोक्रेट्स व डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति शुकाव रखने वाले लोगों (56 प्रतिशत) की रिपब्लिकनस या रिपब्लिकन रूझान वाले लोगों (48 प्रतिशत) की तुलना में भारत के प्रति ज्यादा सकारात्मक सोच है। भारत की वैश्विक स्थिति को देखते हुए 64 प्रतिशत अमेरिकन मानते हैं कि विश्व में भारत का प्रभाव नहीं बदला है पर 23 प्रतिशत मानते हैं कि भारत का प्रभाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक के बाद तमिलनाडू भी "ओपन मार्केट" से चावल खरीदने को मजबूर हुआ

-लक्ष्मण वेंकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। कर्नाटक के गरीब लोग फिलहाल 10 किग्रा मुफ्त चावल पाने से वंचित हो गये हैं क्योंकि भारतीय खाद्य निगम ने, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत, राज्य को चावल बेचने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करने, अन्न भाग्य 2.0 स्कीम लागू करने के लिये, चावल की अतिरिक्त मात्रा की तलाश में है। यह स्थिति केवल कर्नाटक की ही नहीं है, ठीक यही स्थिति इसके

- दोनों राज्यों को बी.पी.एल. परिवारों को "फ्री" चावल देने की उनकी स्कीम के लिये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफ.सी.आई.) ने चावल देने से इन्कार कर दिया है।
- केन्द्र सरकार के दबाव में एफ.सी.आई. ने यह निर्णय लिया है, अतः यह दोनों राज्यों में यह राजनीतिक मुद्दा बन रहा है।
- केन्द्रीय सरकार पर, दक्षिण भारत विरोधी रवैया व सोच रखने का आरोप लगा रही हैं स्थानीय पार्टियाँ।
- भाजपा की दक्षिण भारत में जड़े जमाने की चेष्टा को इस प्रचार से धक्का लगेगा।

मूल्य पर चावल की तलाश के लिये मजबूर हो गया है। इस समय तमिलनाडू सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन नेशनल को-ऑपरेटिव कन्स्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एन.सी.सी.एफ.) तथा अन्य राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़ से चावल खरीदने के लिये मोल-भाव कर रहा है। तमिलनाडू को अपनी अपेक्षित वार्षिक जरूरत को पूरा करने के लिये, कुल मिलाकर 6 लाख टन अतिरिक्त चावल खरीदने की जरूरत है।

जब कॉर्पोरेशन को विभिन्न स्रोतों से चावल के भाव की जानकारी मिल जायेगी, उसके बाद ही तमिलनाडू सरकार चावल खरीद के बारे में कोई निर्णय ले पायेगी। तमिलनाडू पहले भी अन्य राज्यों से चावल खरीदा रहा है। दिसम्बर 2022 से मार्च 2023 के बीच, इस राज्य ने अकेले एन.सी.सी.एफ. से ही 3 लाख टन चावल खरीदे थे। हो सकता है कि केन्द्र चावल बेचने से इन्कार करने के मामले में सही हो तथा उसे पास ऐसा करने के उचित कारण हों, लेकिन लोकसभा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पड़ोसी राज्य तमिलनाडू की भी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफ.सी.आई.) ने इस राज्य को भी ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत चावल बेचने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडू में भी एक ऐसी पार्टी का शासन है, जो केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की विरोधी है। तमिलनाडू को केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य रूप से 2.97 लाख टन चावल आवंटित किये जा रहे हैं जिससे केन्द्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पी.डी.एस. के अन्तर्गत चावल देने की

अपनी बाध्यता का निर्वहन कर सके, लेकिन राज्य को अपनी मुफ्त चावल योजना को आसानी से संचालित करने के लिये 50,000 टन अतिरिक्त चावल की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार का कहना है कि राज्यों को अतिरिक्त चावल नहीं बेच सकती, क्योंकि उसे किसी भी आर्कस्मिक परिस्थिति तथा कीमतों को यथास्थिति में बनाये रखने के लिये चावल के बड़े एवं सुरक्षित भंडार की आवश्यकता है। ठीक कर्नाटक की तरह ही, तमिलनाडू भी वहन करने योग्य

अमेरिकन ड्रोन मदद करेंगे भारतीय सेना की

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। हिमालय के दूरस्थ क्षेत्रों में, भारत के लिए "हाई प्राइऑरिटी मिशन" पर तैनात ड्रोन आकाश में चक्कर लगा रहे हैं, चीन व भारत की सीमा पर चीन की गतिविधियों

- विवादास्पद भारत-चीन सीमा पर घुसपैठ करने वाले चीन के सैनिकों को ट्रैक करने के लिये भारतीय सेना को जल्दी ही अमेरिकन ड्रोन मिल जायेंगे। प्र.मंत्री मोदी ने इस संबंध में 3 अरब डॉलर की डील पर हस्ताक्षर किए हैं।

पर नजर रखने के लिए। तीन अरब डॉलर की इस खरीद की घोषणा मोदी के वॉशिंगटन दौर के दौरान की गई। वॉशिंगटन स्ट्रीट जर्नल ने कहा, कुछ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल "कॉर्नर्ड" हुए पटना सम्मेलन में

यह घटना उल्लेखनीय है, क्योंकि यह उस माहौल का प्रतीक है, जो पटना के "विपक्ष सम्मेलन" में दिखा

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। बिहार की राजधानी पटना में कल हुई 16 गैर एन.डी.ए. विपक्षी नेताओं की चार घंटे तक चली मीटिंग में 32 नेताओं के शब्दों में 2024 के आम चुनावों में भाजपा को हराने की अभूतपूर्व इच्छा साफ दिखाई दे रही थी।

मीटिंग का संदेश और भी ज्यादा सारार्थक एवं विश्वसनीय हो सकता था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविन्द केजरीवाल की भूमिका ने संदेह पैदा कर दिया। उनकी इस मांग में मीटिंग में असामंजसपूर्ण स्थिति ला दी कि कांग्रेस को इस मीटिंग में ही अध्यादेश के मुद्दे पर अपना रूख स्पष्ट कर देना चाहिये। गनीमत यही रही कि उन्होंने अपनी इस धमकी पर अमल नहीं किया कि अगर कांग्रेस उनकी मांग नहीं मानी

- नेताओं का रूख अडियल नहीं था, वरन् काफी लचीला था, नेता आपस में एडजस्टमेंट करने के मुद्दे में दिखे।
- उदाहरण के लिये, कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया, पर खड़गे सबके बाद बोले।

तो वे वॉकआउट कर जायेंगे। केजरीवाल के इस अपवाद को छोड़कर, मीटिंग में हर प्रकार से लचीलापन, सद्भाव एवं ईमानदारी दिखाई दी क्योंकि ज्यादातर नेता सीटों के समायोजन में कुछ लेने तथा कुछ देने के लिये तैयार थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भाजपा से होने वाली चुनावी लड़ाई सीधी तथा वन-टु-वन हो जाए। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, सबसे पहले कांग्रेस से बोलने को कहा गया लेकिन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सभी नेताओं को सुनने के बाद,

अंत में बोलना ज्यादा उचित समझा। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री तथा जे.डी. (यू) प्रमुख नीतीश कुमार बोले तथा उन्होंने इस मीटिंग को विशाल विपक्षी एकता की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने कहा, वर्ष "2024 नजदीक आने पर, इस गठबंधन में और भी पार्टियाँ शामिल होंगी।" आर.जे.डी. प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को नेतृत्व करना चाहिये तथा अन्य पार्टियों को अपना समर्थन प्रदान करना चाहिये। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हरियाणा में अकेले लड़ेगी भाजपा लोकसभा चुनाव

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी दस लोकसभा सीटों पर चुनाव

- भाजपा ने तय किया है कि, चौटाला की जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं दी जायेगी। पार्टी नेतृत्व को लगता है, हरियाणा में चौटाला की पार्टी की वजह से भाजपा की छवि खराब हुई है।

लड़ने का निर्णय लिया है, जो अपने सहयोगी दल, सन् 2018 में गठित, जननायक जनता पार्टी (जे.पी.पी.) को एक भी सीट नहीं देगी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

श्री सीमैंट देश में सबसे बड़ी कम्पनी बनी कॉरपोरेट घोटालों की दृष्टि से?

श्री सीमैंट का यह घोटाला 23 हजार करोड़ रु. से अधिक का माना जा रहा है

अजमेर/ब्यावर/मसूदा, 24 जून (निसं)। श्री सीमैंट लिमिटेड कंपनी के अंधेरी देवरी प्लांट (मसूदा), गोल्टी जिले के रास, नवलगाढ़ के गोठड़ा प्लांट व जयपुर, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ सहित 24 स्थानों पर हुई आयकर विभाग की कार्यवाही में 23 हजार करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। श्री सीमैंट ग्रुप के काले कारोबार का खुलासा, देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला माना जा रहा है, जिसमें, 23000 करोड़ रुपए के फर्जीबाड़े के दस्तावेज जन्त किए गए हैं। आयकर विभाग द्वारा की गई छापे की कार्यवाही में सामने आया है कि,

प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रुपए का फर्जीबाड़ा किया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय से फर्जी एग्रीमेंट भी किए गए। फर्जी एग्रीमेंट से केंद्र और राज्य सरकार को भी चूना लगाया गया है। आयकर विभाग के छापे के बाद से ग्रुप संचालक फरार हैं और प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस ग्रुप के सदस्यों से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी होने से इन्कार कर दिया। वहीं, ग्रुप के चेयरमैन एच.एन. बांगड और वाइस चेयरमैन प्रशांत बांगड छापेमारी के

बाद से बाहर निकल गए हैं। आयकर विभाग की कार्यवाही से मचे हड़कंप के बाद से मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अखोरी, नितिन देसाई फरार हैं। डायरेक्टर श्रीकांत सोमानी और सी.एफ.ओ. सुभाष जाजू भी फरार हैं। ग्रुप के संचालक व ग्रुप के चेयरमैन एच.एन. बांगड

अब तक हुई जांच से पता चला है कि, कंपनी में प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रुपए का फर्जीबाड़ा किया गया। कई प्रकार की टैक्स चोरी करने के लिए सरपंच, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय से फर्जी एग्रीमेंट्स भी किए गए। इन फर्जी एग्रीमेंट्स के जरिये केन्द्र और राज्य सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है।

डायरेक्टर नीरज अखोरी, डायरेक्टर नितिन देसाई, डायरेक्टर श्रीकांत सोमानी और सी.एफ.ओ. सुभाष जाजू से भी आयकर अधिकारियों का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। आयकर अधिकारियों ने फरार हुए कॉरपोरेट के अधिकारियों से संपर्क करने का भरसक प्रयास किया और इनके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया परंतु ग्रुप के किसी भी सदस्य के पास इनकी जानकारी नहीं होने से अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि फरार हुए अधिकारी कहाँ और किस जगह पर हैं। बहरहाल आयकर विभाग की कार्यवाही लगातार

जारी है। जानकार सूत्रों की मानें तो, आयकर विभाग जल्द ही रियल एस्टेट, माईस और अन्य बड़े व्यापारियों पर भी छापेमारी कर सकता है। आयकर विभाग ने हाल ही में अपने तकनीकी संसाधनों को मजबूत करते हुए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण कराया है, जिसमें कुछ ही दिनों की जांच पड़ताल में पता चल जाता है कि, सरकार को कितने राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। देश के इस सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटाले को लेकर संभवतः सोमवार को आयकर विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।

खड़गे की नई टीम की घोषणा शीघ्र ही होगी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी नई टीम के गठन के लिए तैयार हैं, जिसमें युवाओं को जिम्मेदारी देने के साथ-साथ तकरीबन आधा दर्जन राज्य अध्यक्षों को बदला जा सकता है।

- सूत्रों का कहना है कि, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अधिकांश पदों पर नियुक्तियाँ फाइनल कर ली हैं। नई टीम का गठन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि, विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो गई है और खड़गे सभी वर्गों व क्षेत्रों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)